

भारत सरकार  
इस्पात मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1640  
08 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात की खपत

1640. श्री राहुल रमेश शेवाले:

श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय औसत की तुलना में ग्रामीण और शहरी भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या केन्द्र सरकार का देश के ग्रामीण भागों में इस्पात की खपत में वृद्धि करने और इस संबंध में कुछ नीतियां लाने के लिए कोई कार्य योजना बनाने का विचार है; और
- (ग) क्या सरकार की हरित इस्पात अथवा निम्न कार्बन इस्पात विनिर्माण की ओर बढ़ने और भारत को विनिर्माण हब बनाने की दिशा में कोई कार्य योजना प्रस्तावित है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान तैयार इस्पात की ग्रामीण, शहरी और समग्र प्रति व्यक्ति खपत का विवरण नीचे दिया गया है:-

भारत में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत

वर्ष	मात्रा (किग्रा में)		
	ग्रामीण	शहरी (ई)	समग्र
2018-19	19.1	182	74.4
2019-20	20.3	185	74.7
2020-21	21.5	170	70.0
2021-22 (अप्रैल-नवंबर)	22.8	176	72.3

स्रोत: जेपीसी; ई= अनुमानित

(ख): इस्पात मंत्रालय ने देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ इस्पात के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस्पात वस्तुओं के प्रयोग के लाभ जैसे कि सामुदायिक/सामान्य सुविधा क्षेत्रों में इस्पात प्रधान संरचनाएं, जल भंडारण सुविधाएं, अन्न भंडारण साइलो, घरेलू जल भंडारण ड्रम आदि के बारे में वेबिनार आयोजित किए गए। अनुमानित लागत के साथ इस्पात की संरचना वाले आवास विन्यासों के मानकीकृत डिजाइन और ले-आउट, जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-जी) वाले घरों में अपनाया गया है, को विकसित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। इस्पात सीपीएसई अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने ग्रामीण विक्रेताओं को नियुक्त किया है और विभिन्न गतिविधियों में भी लगे हुए हैं, जिनका विशिष्ट रूप से लक्ष्य ग्रामीण भारत को इस्पात के उपयोग के बारे में समझाना है।

(ग): भारतीय लौह एवं इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। इस्पात कंपनियाँ वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार की गतिविधियों के आधार पर अपने स्वयं के निर्णय लेती हैं। विगत वर्षों में, इस्पात उद्योग ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान को अपनाकर इस्पात का लागत-प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन किया है। सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकियों (बीएटी) को व्यापक रूप से अपनाने के साथ भारतीय इस्पात उद्योग ने विशिष्ट ऊर्जा खपत को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे उत्सर्जन तीव्रता में आनुपातिक कमी आई है। भारतीय इस्पात उद्योग की औसत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तीव्रता 2005 में 3.1 टी/टीसीएस से कम होकर 2020 तक करीब 2.6 टी/टीसीएस हो गई है। देश में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु, सरकार द्वारा घोषित हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन में लौह एवं इस्पात क्षेत्र एक हितधारक है।

\*\*\*\*